

ए.एस.ई.एम. सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी

24 अक्टूबर, 2008

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट तीन विफलताओं के कारण उत्पन्न हुआ है:

- (क) बड़े विकसित देशों में विनियामक और पर्यवेक्षीय विफलता,
- (ख) निजी वित्तीय संस्थानों में जोखिम प्रबंधन की विफलता,
- (ग) बाजार अनुशासन तंत्र की विफलता ।

ये मेरे विचार नहीं हैं, अपितु ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशिष्ट प्रबंध निदेशक के विचार हैं, जिनसे मैं सहमत हूँ ।

हमें निष्पक्ष रूप में यह विश्लेषण करना होगा कि ये विफलताएं कैसे और क्यों इतने उग्र रूप में हमारे समक्ष आ खड़ी हुई हैं । ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए नए नियम बनाना आवश्यक हो गया है ।

यह एक कटु सत्य है कि वैश्वीकरण के इस युग में हमारे पास बहुत ही साधारण अर्थ व्यवस्था हैं, किंतु इसे कारगर बनाने के लिए वैश्विक शासन व्यवस्था का सहयोग प्राप्त नहीं है ।

नकदी का परिणामी संकट, अनुपयुक्त परिसंपत्तियों के जमा होने, पूंजी की कमी, और आत्मविश्वास की कमी से वास्तविक अर्थव्यवस्था बिखरने का खतरा पैदा हो गया है, जो वस्तुओं की मांग में कमी तथा सेवाओं विशेष रूप से निर्यात में कमी के रूप में सामने आया है । व्यापार में कमी तथा आपूर्तिकर्ताओं के विश्वास में कमी अन्य संकटों पर हावी हो गई है जिसके कारण खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे बजट पर बोझ पड़ा है और भुगतान का संतुलन बिगड़ गया है, इससे बहुत से विकासशील देशों में मुद्रास्फीति और जीवन मापन लागत में वृद्धि हुई है ।

विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कम से कम 30 ऐसे विकासशील देशों की पहचान की है जिनके भुगतान की शेष राशि के लिए इस वित्तीय संकट की वजह से गंभीर संकट पैदा हो जाएगा ।

हमें विश्व भर के ऋण बाजार की तत्काल अवरोध रहित करने का कार्य करना चाहिए । इस ऋण बाजार में विश्वास जगाने के उपाय स्वरूप समन्वित वैश्विक कार्रवाई अनिवार्य है ।

विकासशील देशों के दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा प्रभावित देशों को अधिक शीघ्रता से और बड़ी मात्रा में न्यून सेवा शर्तों तथा अधिक लचीलेपन के साथ सहायता प्रदान करने के आशय से उपयुक्त आकस्मिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है ।

पर्याप्त विदेशी विनिमय वाले देश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को उनके प्रचालनों को वित्त प्रदान करने के लिए उपयुक्त शर्तों पर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं ।

प्रतिकूल चक्रीय साधन के तौर पर, विकासशील देशों में यदि वर्द्धित अवसंरचना निवेश को आई बी आर डी और क्षेत्रीय विकास बैंकों जैसे बहु आयामी वित्तीय संस्थानों से वर्द्धित संसाधन प्रवाह का सहारा मिल जाए तो यह एक शक्तिशाली स्थायीकारी का कार्य कर सकता है ।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थानों के पक्ष में विशेष आहरण अधिकारों के नए सिरे से आबंटन के माध्यम से नकदी बढ़ाने के अत्यधिक शक्तिशाली तरीके अपनाने पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

वित्तीय प्रणाली में सुधार तथा पुनर्निर्माण एक सामूहिक अंतरराष्ट्रीय प्रयास होना चाहिए क्योंकि देशों की सीमाएं वित्तीय संस्थानों को अधिक समय तक सीमित नहीं रख सकती या वित्तीय उतार-चढ़ावों से बचे नहीं रहने दे सकती । पिछले तीन दशकों में सीमा पार निवेश, व्यापार और बैंकिंग में वृद्धि के चलते विश्व के सभी देशों को एक वैश्विक मॉनीटरिंग प्राधिकरण की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए जिसे सतत रूप से समन्वित होते विश्व, जिसमें हम जी रहे हैं, में वैश्विक पर्यवेक्षण और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके ।

सुधार संबंधी कार्यवृत्त तैयार करते समय हमें अत्यधिक अनुमान संबंधी क्रियाकलापों की आर्थिक रूप से विनाशकारी भूमिका के संबंध में जॉन मेयनार्ड कइंस की सूक्ति भी याद रखनी चाहिए:-

" अटकलबाज उद्यम की स्थिर नदी पर बुलबुलों की भांति कोई नुकसान भले ही न करें । किन्तु वह स्थिति गंभीर होगी जब अटकलबाजी के भंवर में उद्यम ही बुलबुला

बन जाए । जब किसी देश का पूंजीगत विकास कैसीनो के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होता है तो उस विकास को दुर्विकास माना जाता है ।

स्पष्टतः, वहाँ विनियामक तथा पर्यवेक्षणीय अधिकारों की भारी विफलता होती है। अटकलबाजों को काफी लम्बी अवधि तक उन्मुक्त रूप से कार्य करने का अवसर मिला है । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बनाए रखी । बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कारगर बहुपक्षीय पर्यवेक्षण की अवांछनीय विफलता रही है और यह विफलता विशेष रूप से उनके वित्तीय बाजारों के क्रियाकलापों के संबंध में हैं ।

भारत की बैंक प्रणाली मजबूत और पर्याप्त पूंजीगत है । इसकी परिसंपत्ति उस प्रकार की नहीं हैं जिससे इस संकट को बढ़ावा मिला हो । निर्यात मांग और पूंजी के अंतर्वाह की वैश्विक मंदी के बावजूद हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 7 से 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी । हमने इस प्रणाली में नकदी को बढ़ाया है ।

हम महसूस करते हैं कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली गहन संकट में हो तो हम इससे अछूते नहीं रह सकते । विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी के बर्हिगमन के कारण हमारे स्टॉक बाजार और रुपये की विनिमय दर दबाव बढ़ा है आज नहीं तो कल वास्तविक अर्थव्यवस्था को आघात पहुँचना ही है ।

अतः हम विश्व की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के कारगर और प्रगतिशील उपाय ढूँढने के लिए विश्व समुदाय को सहयोग और समन्वय प्रदान करने की सच्ची अभिलाषा रखते हैं ।

धन्यवाद

* * * *